



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022020-216247
CG-DL-E-18022020-216247

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2020/माघ 28, 1941

No. 677]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2020/MAGHA 28, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 742(अ).—केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रथम अनुसूची के मद 6 के अधीन आच्छादित ऐसे उद्योग की सेवाएं, जो खाद्य पदार्थ में लगे हुए हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा होगी ;

और, केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2439(अ), तारीख 9 जुलाई, 2019 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 9 जुलाई, 2019 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि और छह महीने के लिए उक्त उद्योग को लोकोपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खाद्य पदार्थों में लगे हुए उद्योग को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त अगले छह महीने के लिए लोकोपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/5/91-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2020

S.O. 742(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in Food Stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 9th July, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2439(E), dated 9th July, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in Food Stuffs to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the date of publication of the notification.

[F. No. S-11017/5/91-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.